बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 11 अंक 303

बुनियादी क्षेत्र की चिंता

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की पहली सरकार ने बुनियादी विकास को प्राथमिकता दी थी और उसे देश में रोजगार निर्माण और आर्थिक वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण इंजन बनाया था। पिछले चार बजट को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी इन बातों पर ध्यान दिया गया है। परंतु हालिया अंतरिम बजट में पूरा ध्यान समाज के वंचित वर्ग पर रहा है। काफी हद तक सरकार की बजट प्राथमिकता चुनावी दबाव से संचालित रही है। चुनाव के पहले लगभग हर राजनीतिक दल के सुर लोकलुभावन हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकार का ध्यान इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय समर्थन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना और 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले लोगों को आयकर में छूट पर केंद्रित रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को अपने संसाधनों को तार्किक बनाने की आवश्यकता पड़ी। पीएम-किसान और आयकर छूट जैसी योजनाओं की वजह से पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को समायोजित करने के लिए सरकार को बुनियादी विकास की योजनाओं के लिए किए जाने वाले बजट आवंटन में कमी करनी पड़ी।

परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बीते पांच वर्ष के दौरान सरकार की उपलब्धियां नहीं दर्शाईं। उन्होंने उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का खासतौर पर उल्लेख किया। इस योजना के परिणामस्वरूप देश में परिचालित हो रहे हवाई अड्डों की संख्या 100 का स्तर पार कर चुकी है। यही वजह है कि घरेलू विमान यात्रियों की संख्या बीते पांच वर्ष में बढ़कर दोगुनी हो गई। उन्होंने सुरक्षा के मामले में भारतीय रेल की सफलता का भी जिक्र किया। सफलता की इस दास्तान का एक बड़ा पहलू यह तथ्य भी है कि ब्रॉड गेज पर मौजूद तमाम मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है। इन बदलावों की बदौलत देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंच की गति तेज हुई है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश अब देश के विमानन मानचित्र पर नजर आने लगा है और मिजोरम तथा मेघालय जैसे प्रांत पहली बार देश के रेलवे मानचित्र पर दिखने लगे हैं। एक अन्य घटना जो पहली बार घटी है वह यह कि कोलकाता से वाराणसी के बीच पहली बार जलमार्ग से माल ढुलाई की शुरुआत की गई। सड़क और रेल के मोर्चे पर भी पीछे मुड़कर देखने पर खुश होने की कई वजह नजर आती हैं। प्रति दिन लगभग 27 किलोमीटर का राजमार्ग निर्माण कार्य हुआ है। हाल के महीनों में यह गति और तेज हो गई है। हमारा देश राजमार्ग निर्माण की गति के मामले में दुनिया में सबसे आगे है।

इन सफलताओं के बावजूद अंतरिम बजट इस मोर्चे पर निराश करता है। साफ देखा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित पुनर्वितरण योजनाओं ने इस क्षेत्र के आवंटन पर असर डाला है। ऐसे में हालांकि रेलवे को 1.57 लाख करोड़ रुपये का उच्चतम पूंजीगत व्यय आवंटित हुआ है और इसे 64,587 करोड़ रुपये का उच्च बजट समर्थन मिला है लेकिन सड़क और विमानन क्षेत्र इतने भाग्यशाली नहीं हैं। उदाहरण के लिए सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मिलने वाली बजट राशि में 631 करोड़ रुपये से अधिक की कमी की है। यही वजह है कि प्राधिकरण को अब उधारी और सड़क परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की मदद से फंड जुटाने की कवायद करनी होगी। इसी प्रकार सागरमाला परियोजना के लिए बजट आवंटन को वित्त वर्ष 2020 के लिए कम करके 550 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2019 में भी सरकार 600 करोड़ रुपये के आवंटन में से केवल 381 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी थी।

बिनय सिन्हा

चीन-जापान की करीबी और भारत की दूरी

भारत ऐसा कोई अवसर नहीं मुहैया करा पा रहा है जिसकी तुलना चीन की `मेड इन चाइना 2025' पहल से की जा सके। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **श्याम सरन**

अमेरिका और चीन के कारोबारी युद्ध की बातों के बीच हम एक अहम घटना पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में चीन और जापान के तनावपूर्ण राजनीतिक रिश्तों की बर्फ कुछ हद तक पिघलती नजर आई है और उनके बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों में नई जान आ रही है। चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग मई 2018 में जापान की यात्रा पर गए थे। वह एक शुरुआत थी जिसके बाद अक्टूबर 2018 में जापानी प्रधानमंत्री चीन गए। यह 11 वर्ष में पहला मौका था जब कोई जापानी प्रधानमंत्री चीन गया था। दोनों पक्षों के तनावपूर्ण रिश्तों में नरमी की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने व्यापारिक मसलों पर इन दोनों देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चीन के लिए जापानी उद्योग एवं व्यापार का महत्त्व यह है कि अमेरिकी बाजारों और उन्नत तकनीक तक उसकी पहुंच लगातार सीमित होती जा रही है। उधर जापान कुछ सीमाओं के साथ एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। हाल के दिनों में हुआवेई का जापानी दूरसंचार बाजार से बाहर होना ऐसी ही एक घटना है।

चीन और जापान के रिश्तों में तनाव नई सहस्राब्दी के आगमन के समय क्षेत्रीय और सुरक्षा मसलों को लेकर हुआ। सन 2012 में विवादित सेंकाकू द्वीप को लेकर हालात बहुत नाजुक हो गए थे। वर्ष 2012 में चीन में जापानी एफडीआई 740 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था लेकिन अगले कुछ वर्षों में इसमें गिरावट आई और यह 2016 में 310 अरब डॉलर रह गया।

सालाना सर्वेक्षणों की बात करें तो अधिक से अधिक जापानी कंपनियां चीन से बाहर निकलने पर विचार कर रही थीं जबकि वहां विस्तार करने की इच्छा रखने वाली कंपनियां बहुत कम थीं। दोनों देशों के बीच अत्यंत तनावपूर्ण रिश्तों के कारण जापान ने अपना निवेश चीन के अलावा अन्य क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया। यही वह वक्त था जब जापान ने भारत की ओर ध्यान दिया। यह ध्यान सुरक्षा साझेदार के रूप में भी था और जापानी व्यापार और निवेश के केंद्र के रूप में भी। तेजी से विकसित होती भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन के समतुल्य पेशकश वाला बाजार माना जाने लगा। भारत में जापानी एफडीआई 2006-07 के 8.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 470 करोड़ डॉलर हो गया। चीन में कुल मिलाकर 10,000 करोड़ डॉलर की जापानी पूंजी है। भारत में यह केवल 2,500 करोड़ डॉलर है। अब जबकि चीन एक बार फिर जापानी निवेश के लिए उपयुक्त केंद्र बनकर उभर रहा है तो कहा जा सकता है कि भारत पर हाशिये पर चले जाने का खतरा मंडरा रहा है। चीन में जापानी एफडीआई 2017 में सुधरकर 320 करोड़ डॉलर हो गया और माना जा रहा है कि इसमें आगे और सुधार होगा। जापान के बाह्य व्यापार संगठन (जेट्रो) के एक अधिकारी के मुताबिक, 'हमारा मौजूदा निष्कर्ष यह है कि जापनी कारोबार चीन में निवेश को लेकर आगे और सकारात्मक रहेगा।'

जापान-चीन व्यापार में भी वर्ष 2012 के बाद आई गिरावट अब पलटी है और सुधार देखने को मिल रहा है। 2017 में यह करीब 30,000 करोड़ डॉलर रहा। भारत-जापान व्यापार में हाल के वर्षों में गिरावट आई है और यह 2012-13 के 1,850 करोड़ डॉलर से घटकर 2016-17 में मात्र 1,350 करोड़ डॉलर रह गया। इसी अवधि में भारतीय निर्यात 610 करोड़ डॉलर से कम होकर 380 करोड़ डॉलर रह गया।

जापान का कारोबारी जगत चीन की मेड इन चाइना 2025 पहल को एक बड़े अवसर के रूप में देखता है। इस पहल में 10 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है जिनमें कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और क्वांटम कंप्यूटिंग आदि शामिल हैं। चीन का लक्ष्य सन 2025 तक इन तमाम क्षेत्रों में अच्छी काबिलियत हासिल करने का है। जापान इन क्षेत्रों में पहले ही अहम काबिलियत हासिल कर चुका है। हाल ही में जापान की रोबोट निर्माता कंपनी यासकावा और चीन की वाहन कंपनी चेरी ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को लेकर समझौता किया है। नैशनल पैनासोनिक के शांघाई स्थित शोध एवं विकास केंद्र ने चीन की अलीबाबा और बायडू से कनेक्टेड डिवाइस और नई पीढ़ी के वाहनों के इंस्ट्रूमेंट पैनल बनाने के लिए समझौता किया है। अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप के देश जहां मेड इन चाइना पहल को अपने तकनीकी दबदबे के लिए चुनौती के रूप में देख रहे हैं, वहीं जापान का रुख इसके उलट है। भारत के पास इसके समतुल्य अवसर नहीं है।

सन 2013 में जापान ने चीन की बेल्ट ऐंड रोड पहल का विरोध किया था। परंतु 2015 में उसने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में सहयोग के साथ प्रतिक्रिया दी और एशिया तथा अफ्रीका के देशों में वित्तीय सहायता का व्यवहार्य तथा पारदर्शी विकल्प उपलब्ध कराया। सन 2017 में भारत और जापान ने मिलकर एशिया-अफ्रीका इकनॉमिक ग्रोथ कॉरिडोर (एएईजीसी) की घोषणा की ताकि एशिया और अफ्रीका के देशों में बुनियादी विकास को संयुक्त फंडिंग की जा सके। बहरहाल, जून 2018 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजे आबे ने इसके लिए चीन का हाथ थाम लिया। अक्टबूर 2018 में उनकी चीन यात्रा के दौरान ऐसी 50 परियोजनाओं की घोषणा की गई। इनमें थाईलैंड की एक रेल परियोजना भी शामिल थी। जापान अब बेल्ट रोड पहल में चीन के साथ है।

जापान का कारोबारी जगत भारत में निवेश के माहौल को लेकर भी चिंतित रहता है। भारत-जापान बिज़नेस लीडर्स की हालिया संयुक्त रिपोर्ट में जापानी पक्ष ने भारत सरकार से मांग की कि वह जीएसटी व्यवस्था को सुसंगत और गतिशील बनाए तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को भी ठीक करे। इसके अलावा कर व्यवस्था को सुधारने, उसमें आंतरिक स्तर पर निरंतरता लाने आदि जैसी बातें भी कही गईं। इसमें मास्टर फाइल की जरूरतों की समीक्षा, श्रम सुधारों को मजबूत बनाना और उनमें संशोधन करना, डेटा स्थानीयकरण को लेकर नियमों को सहज कर डेटा का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करना, बुनियादी विकास को बढ़ावा देना, परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता लाना, कानूनी और संस्थागत ढांचों के प्रवर्तन में निरंतरता उत्पन्न करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आम नियमों का विकास करना और उनका डिजिटलीकरण करना आदि तमाम बातें शामिल हैं।

आज चीन में एफडीआई को लेकर कोई बहुत बेहतर शर्तों की पेशकश नहीं है लेकिन इसके बावजूद जापान को भारत के बजाय चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ कारोबार करना ज्यादा रास आ रहा है, उसे इसमें अधिक सहजता महसूस हो रही है।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव और वर्तमान में सीपीआर के वरिष्ठ फेलो हैं। लेख में प्रस्तुत विचार पूरी तरह निजी हैं।)

सब्सिडी का बोझ अनुमान से अधिक रहने के आसार

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

अप्रैल-नवंबर, 2018 के दौरान सब्सिडी पर खर्च की औसत दर यह संकेत देती है कि वित्त वर्ष 2018-19 में इन पर खर्च संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक रहेगा

पिछले शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2018-19 के कुछ अनुमानों को संशोधित किया गया है, जिन्हें लेकर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सरकार का जवाब यह है कि वित्त मंत्रालय के पास ऐसे ब्योरे और आंकड़े उपलब्ध हैं, जो उसे ये आंकड़े जारी करने का भरोसा देते हैं। यह बयान आश्वस्त करने वाला होना चाहिए। आखिरकार ये संशोधित आंकड़े सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के अपने संशोधित लक्ष्य को हासिल करने में अहम होंगे। यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 फीसदी है।

इसके बावजूद इन आंकड़ों की हकीकत की पड़ताल उपयोगी साबित हो सकती है। सबसे पहले हमें देश में प्रमुख सब्सिडी पर खर्च को देखना चाहिए। खाद्य सब्सिडी का संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये है, जबकि इसका बजट अनुमान 1.69 लाख करोड़ रुपये पेश किया गया था। अंतरिम बजट से पहले नवंबर 2018 तक का खाद्य सब्सिडी का मासिक आंकड़ा उपलब्ध था। इस आंकड़े के अनुसार अप्रैल से नवंबर तक खाद्य सब्सिडी का बिल 1.42 लाख करोड़ रुपये या करीब 17,800 करोड़ रुपये प्रतिमाह था। अगर यह मानकर चलते हैं कि चालू वित्त वर्ष के शेष चार महीनों में खाद्य सब्सिडी की औसत मासिक दर यही बनी रही तो कुल खाद्य सब्सिडी बिल बढ़कर 2.14 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। यह अंतरिम बजट के संशोधित अनुमान से करीब 42,000 करोड़ रुपये अधिक होगा।

उर्वरक सब्सिडी के भी दो अहम हिस्से हैं। अंतरिम बजट दर्शाता है कि यूरिया सब्सिडी का संशोधित अनुमान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 44,985 करोड़ रुपये है। यह बजट अनुमान 44,989 करोड़ रुपये से मामूली कम है। अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान यूरिया सब्सिडी पर खर्च 33,294 करोड़ रुपये रहा है, यानी हर महीने 4,162 करोड़ रुपये। अगर चालू वर्ष के शेष चार महीनों में भी खर्च इसी दर से बढ़ा तो कुल यूरिया सब्सिडी बिल बढ़कर 49,941 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा, जो अंतरिम बजट में दिए गए संशोधित अनुमान के आंकड़े से करीब 4,956 करोड़ रुपये अधिक होगा।

इसी तरह पोषण आधारित उर्वरकों का सब्सिडी बिल 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 25,090 करोड़ रुपये दिखाया गया है, जो एक साल पहले बजट अनुमानों में दिए गए आंकड़े के समान है। लेकिन इस मद पर अप्रैल-नवंबर 2018 की अवधि में 20,152 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं यानी हर महीने 2,159 करोड़ रुपये। अगर वर्ष के शेष चार महीनों में खर्च इसी रफ्तार से बढ़ा तो पोषण आधारित उर्वरकों की सब्सिडी का सालाना बिल बढ़कर 30,228 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। यह अंतरिम बजट में पेश किए गए संशोधित अनुमान से 5,138 करोड़ रुपये अधिक होगा।

अंतरिम बजट में पेट्रोलियम सब्सिडी बिल का संशोधित अनुमान 24,833 करोड़ रुपये है, जो इसी वर्ष के बजट अनुमान 24,933 करोड़ रुपये से कम था। चालू वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं, इसलिए रसोई गैस और केरोसिन के सब्सिडी बिल बढ़ने चाहिए। असल में चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 23,142 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है यानी हर महीने 2,893 करोड़ रुपये का खर्च आया है। अगर चालू वित्त वर्ष के शेष चार महीनों में पेट्रोलियम सब्सिडी का खर्च इसी रफ्तार से बढ़ा तो कुल बिल बढ़कर 34,713 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। यह अंतरिम बजट के संशोधित अनुमान से 9,880 करोड़ रुपये अधिक होगा।

संशोधित अनुमानों के मुताबिक इन प्रमुख सब्सिडी पर 2018-19 के दौरान कुल 2.66 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह राशि बजट अनुमान 2.64 लाख करोड़ रुपये से मामूली अधिक है। अगर आप अप्रैल से नवंबर 2018 के दौरान इन सब्सिडी पर आए खर्च के आधार पर पूरे साल के खर्च का अनुमान लगाएंगे तो पाएंगे कि खर्च 0.62 लाख करोड़ रुपये अधिक रह सकता है। प्रमुख सब्सिडी का वास्तविक बिल 3.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि इनका संशोधित अनुमान 2.64 लाख करोड़ रुपये ही है।

यह बात ध्यान देने लायक है कि इन सब्सिडी पर खर्च के मासिक आंकड़े नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) हर महीने जारी करता है। निस्संदेह सीएजी के आंकड़े ऑडिट नहीं किए हुए और अस्थायी हैं। इसके अलावा यह भी संभव है कि बीते महीनों के खर्च की रफ्तार हर मामले में लागू न हो। बजट बनाने वालों की सूचनाओं और आंकड़ों तक ज्यादा पहुंच होती है। इनसे उन्हें संशोधित आंकड़े जारी करने का भरोसा मिलने की संभावना है। यह संभव है कि राजकोषीय घाटे के आंकड़े पर इसके असर को कुछ मदों में संशोधित अनुमानों की तुलना में कम खर्च करके बेअसर कर दिया जाए। या इस खर्च के एक हिस्से को अगले साल तक टाल दिया जाए? लेकिन प्रमुख सब्सिडी पर ही संशोधित अनुमान के मुकाबले 0.62 लाख करोड़ रुपये अधिक खर्च होने से सरकार के राजकोषीय मजबूती के कार्यक्रम की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेंगे।

कानाफूसी

मन की बात राहुल से

पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के एक रेस्तरां में छात्रों के एक समूह के साथ चर्चा करते देखे गए। पार्टी ने इस कार्यक्रम का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का जवाब बताया जा रहा है। राहुल ने अपना परिचय देने के बाद कहा, 'अपनी बात राहुल के साथ' कार्यक्रम की पहली कड़ी में आपका स्वागत है। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यह स्वत:स्फूर्त बातचीत थी जहां छात्रों से कहा गया था कि पार्टी के एक नेता उनसे बात करेंगे लेकिन जब उन छात्रों ने राहुल को अपने बीच देखा तो वे चकित रह गए। राहुल ने कहा कि उन्हें लगा कि उन्हें युवाओं से बातचीत करके उनकी सोच के बारे में जानकारी मिलेगी। गौरतलब है कि सन 2014 के आम चुनाव के पहले कांग्रेस का घोषणापत्र जारी करने के पहले भी राहुल ने ऐसी ही चर्चाएं आयोजित की थीं।

बदला दौर

योग गुरु से कारोबारी बने रामदेव के करीबी सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण को पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रीवा स्थित एक विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। रीवा जाने से पहले बालकृष्ण कुछ समय के लिए राजधानी भोपाल के एक वीआईपी अतिथि गृह में रुके। इन मसलों पर गौर करने वालों के मुताबिक बालकृष्ण की यह यात्रा उनकी पिछली कुछ यात्राओं से एकदम अलग रही। पहले उनकी यात्राओं के दौरान राजनेता,मंत्री और नौकरशाह सब उनको घेरे रहते थे। पत्रकार भी बालकृष्ण की एक बाइट लेने के लिए तरसते रहते थे क्योंकि वह मीडिया से बहुत कम ही बात करते थे। परंतु इस बार केवल एक कनिष्ठ सरकारी अधिकारी ही उनसे मिलने अतिथि गृह पहुंचा।

आपका पक्ष

परंपरागत ऊर्जा बनाम रसोई गैस

देश में रसोई गैस के आगमन से पहले परंपरागत ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रामीण भारत में कुछ जगह अभी भी परंपरागत ऊर्जा का ही इस्तेमाल किया जाता है। गांवों की महिलाएं बाग-बगीचे, खेत-खलिहान से जलावन लकड़ी चुनकर लाती हैं। घर में पाले गए मवेशियों के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। इसका उपयोग रसोई में चूल्हा जलाने में किया जाता है। लकड़ी कोयला और खान से निकले कोयले से भी चूल्हा जलाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जगह-जगह पर गोबर के उपले सूखते दिख जाएंगे। छोटे ढाबे और होटलों में कोयले के चूल्हे जलते मिल जाएंगे। ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं लेकिन इसके हानिकारक पहलू भी हैं। चूल्हे से निकलने वाले धुएं से सांस जनित बीमारियां होती हैं। इस बीमारी की चपेट में कितने प्रतिशत लोग आते हैं। इसका कोई आंकड़ा शायद ही उपलब्ध हो। इस चूल्हे से निकलने

केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का मकसद हर घर में रसोई गैस कनेक्शन देना है

वाला धुआं भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। भारत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य पर काम भी कर रहा है। दूसरी ओर सरकार रसोई गैस को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर लोगों को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर में रसोई गैस से खाना पके जिससे महिलाओं को परंपरागत चूल्हे से निकलने वाले धुएं से निजात मिल सके। सरकार की यह पहल सराहनीय है तथा इससे रसोई घर की रौनक भी बढ़ जाती है। घर में खाना पकाना आसान हो गया है तथा परंपरागत चूल्हे को जलने में लगने वाला समय भी बच जाता है। गैस चूल्हा तुरंत जल उठता है लेकिन परंपरागत चूल्हे में लकड़ी, कोयले या उपले को जलने समय लगता है। अगर हम परंपरागत ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो धुआं जनित रोग तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। रसोई में ईंधन के रूप में होने वाला खर्च भी बच सकता है। मवेशियों के गोबर से बने उपले, खेत तथा बाग-बगीचे से निकलने वाले जलावन का समुचित इस्तेमाल किया जा सकता है।

किशोर कुमार, नोएडा

सेवा क्षेत्र का हो विस्तार

रोजगार सृजन के लिए सरकार को देश के सेवा क्षेत्र में नए प्रयोग करने के साथ-साथ उसमें विस्तार करने की जरूरत है। आज कृषि, प्रशासन, बैंक, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, साइबर सुरक्षा, तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्रों में नए पदों पर भर्तियों की आवश्यकता है। केंद्र व राज्य सरकारें भारी तादाद में रोजगार देने वाले उद्योग व नई नौकरियां पैदा करने में नाकाम रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कौशल विकास योजना और लघु उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। युवाओं को नौकरी के लायक बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिये कौशल विकास बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उद्योग व तकनीक संस्थान में बेहतर तालमेल जरूरी है। मोदी सरकार ने कौशल विकास को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर किये थे। लेकिन अब तक उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। ऐसे में योजनाओं की प्राथमिकताओं में बेरोजगारी उन्मूलन को शामिल कर ठोस कदम उठाए जाएं।

आकाश गुप्ता, पटना

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।